राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 11575/2019

गोपीराम यादव पुत्र श्री रामनारायण यादव, उम्र लगभग 53 साल, आमीन अली, 507, रॉयल वर्ल्ड संसार चंद रोड, जयपुर, निवासी सिरसी रोड, झिपुरियो का बाग, सिरसी जयपुर (राजस्थान)

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान सरकार- श्रम विभाग, सचिवालय जयपुर सचिव, के माध्यम से।
2. श्रम आयुक्त एवं सुलह अधिकारी, जयपुर।
3. क्षेत्रीय वन अधिकारी, विश्व वानिकी, झालाना डूंगरी, जयपुर (राजस्थान)
4. वन विस्तार अधिकारी, ग्रास फार्म नर्सरी, खातीपुरा, जयपुर (राजस्थान)

----प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से : श्री कान सिंह राठौड़

माननीय न्यायमूर्ति अनूप कुमार ढंड

<u>आदेश</u>

आदेश सुरक्षित करने की तिथि	:	03.08.2023
आदेश उच्चारित करने की तिथि	:	17.08.2023

<u>रिपोर्टेबल</u>

1. इस याचिका में शामिल कानूनी मुद्दे यह हैं कि "क्या उचित सरकार विलंब के आधार पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 के तहत एक संदर्भ बनाने से इनकार कर सकती है?" क्या सरकार इस प्रश्न का निर्णय करते समय निर्णायक प्राधिकारी की भूमिका निभा सकती है कि कोई संदर्भ दिया जाए या नहीं?

2. इस याचिका को दायर करके, याचिकाकर्ता ने दिनांक 19.12.2011 के आक्षेपित आदेश की वैधता को चुनौती दी है जिसके द्वारा उपयुक्त सरकार ने सेवा समाप्ति के 24 साल बाद विवाद उठाने के आधार पर श्रम न्यायालय को संदर्भ देने से इनकार कर दिया है।

3. याचिकाकर्ता/कर्मचारी ने यह कहते हुए एक औद्योगिक विवाद उठाया कि वह 01.02.1985 को 'बेलदार' के रूप में नियुक्त हुआ था और 28.12.1986 तक उस पद पर काम किया। उनकी उपस्थिति मस्टर रोल में दर्ज की गई थी और उन्होंने एक कैलेंडर वर्ष में 240 से अधिक दिनों तक काम किया है, लेकिन 28.12.1986 को उनकी सेवाएं बिना किसी नोटिस या एक महीने की मजदूरी के भुगतान के मौखिक रूप से समाप्त कर दी गईं। दलील दी गई कि कोई वरिष्ठता सूची तैयार नहीं की गई। अतः, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (संक्षेप में, '1947 का अधिनियम') के प्रावधान के विरुद्ध उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं। याचिकाकर्ता का मामला यह है कि वह अनपढ़ था और उसने प्रतिवादी/नियोक्ता से उसे सेवा में वापस बहाल करने का अनुरोध किया था, लेकिन आश्वासन के अलावा उसे सेवा में वापस लाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया।

4. पार्टियों के बीच सुलह की कार्यवाही की गई लेकिन दोनों पक्षों ने अपने रुख पर अड़े रहने का निर्णय लिया, अतः 27.06.2011 को लेबर इंडस्ट्रियल जयपुर रीजन के समक्ष सुलह विफल हो गई, जिन्होंने अपने पत्र के माध्यम से मामले को आगे बढ़ाने के लिए उपयुक्त सरकार को दिनांक 19.07.2011 को भेज दिया।

5. उपयुक्त सरकार ने विलंब के आधार पर विवाद को श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरण को संदर्भित करने से इनकार कर दिया क्योंकि विवाद 24 साल की विलंब के बाद भेजा गया था और इस अत्यधिक विलंब का कोई उचित स्पष्टीकरण कामगार द्वारा नहीं दिया गया था, अतः, दिनांक 19.12.2011 के आक्षेपित आदेश द्वारा दावे को समयोपरांत दावा' माना गया।

6. याचिकाकर्ता ने दिनांक 19.12.2011 के आक्षेपित आदेश से व्यथित होकर इस न्यायालय के समक्ष यह याचिका प्रस्तुत की है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि औद्योगिक विवाद को उठाने और अधिनियम के तहत संदर्भ मांगने के लिए 1947 के अधिनियम के तहत कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अधिवक्ता का कहना है कि परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 के तहत प्रावधान 1947 के अधिनियम के तहत प्रस्तुत आवेदनों पर लागू नहीं होते हैं। अपने तर्क के समर्थन में, उन्होंने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा रखा है:-

1. अजायब सिंह बनाम सरहिंद सहकारी मार्केटिंग-कम-प्रोसेसिंग सर्विस सोसाइटी लिमिटेड ने 1999(2) एससीटी 667 में प्रकाशित।

2. रघुबीर सिंह बनाम महाप्रबंधक, हरियाणा रोडवेज ने 2014 (10) एससीसी 301 में प्रकाशित।

7. सुनवाई की गई और प्रस्तुतियों पर विचार किया गया।

8. रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन से पता चलता है कि दिनांक 19.12.2011 को आक्षेपित आदेश पारित करके, उपयुक्त सरकार ने विलंब के आधार पर विवाद को श्रम न्यायालय में संदर्भित करने से इनकार कर दिया है और याचिकाकर्ता के विवाद को समयोपरांत' दावा करना माना।

9. प्रश्नगत मुद्दे से निपटने के लिए आगे बढ़ने से पहले 1947 के अधिनियम की धारा 10 के तहत निहित प्रासंगिक प्रावधान को उद्धृत करना फायदेमंद होगा जो बोर्डों, न्यायालयों और न्यायाधिकरणों को विवादों के संदर्भ से संबंधित है। धारा 10 इस प्रकार है:

> "**10. विवादों को बोर्डों, न्यायालयों या अधिकरणों को निर्देश-**
>
> (1) जहां कि समुचित सरकार की यह राय हो कि कोई औद्योगिक विवाद विद्यमान है या उसके होने की आशंका है वहां वह लिखित आदेश द्वारा किसी भी समय-
>
> (क) उस विवाद का समझौता कराने के लिए उसे बोर्ड को निर्देशित कर सकेगी, अथवा
>
> (ख) विवाद से संसक्त या सुसंगत प्रतीत होने वाले किसी मामले को जांच के लिए न्यायालय को निर्देशित कर सकेगी, अथवा
>
> (ग) विवाद को, या विवाद से संसक्त या सुसंगत प्रतीत होने वाले किसी मामले को, यदि वह किसी ऐसे विषय के सम्बन्ध में हो जो द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, न्यायनिर्णयन के लिए किसी श्रम न्यायालय को निर्देशित कर सकेगी, अथवा
>
> (घ) विवाद को, या विवाद से संसक्त या सुसंगत प्रतीत होने वाले किसी मामले को, चाहे वह द्वितीय अनुसूची में चाहे तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी विषय के सम्बन्ध में हो, न्यायनिर्णयन के लिए किसी अधिकरण को निर्देशित कर सकेगी:
>
> परन्तु जहां कि विवाद तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी विषय के संबंध में हो और उससे एक सौ से अधिक कर्मकारों पर प्रभार पड़ना सम्भाव्य न हो वहां यदि समुचित सरकार ठीक समझे तो वह खण्ड (ग) के अधीन श्रम न्यायालय को निर्देश कर सकेगी:
>
> परन्तु यह और कि जहां कि विवाद किसी लोक उपयोगी सेवा के सम्बन्ध में हो और धारा 22 के अधीन सूचना दे दी गई हो, वहां जब तक कि समुचित

सरकार का यह विचार न हो कि सूचना तुच्छतया या तंग करने के लिए दी गई है, या ऐसा करना समीचीन न होगा, वह, इस बात के होते हुए भी कि विवाद की बाबत इस अधिनियम के अधीन कोई अन्य कार्यवाहियां प्रारम्भ हो चुकी हों, इस उपधारा के अधीन निर्देश करेगी:

परन्तु यह और कि जहां विवाद ऐसा है जिसके संबंध में केन्द्रीय सरकार समुचित सरकार है, वहां वह सरकार, विवाद को राज्य सरकार द्वारा गठित, यथास्थिति, श्रम न्यायालय या औद्योगिक अधिकरण को, निर्देशित करने के लिए सक्षम होगी।

(1क) जहां कि केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि कोई औद्योगिक विवाद विद्यमान है या उसके होने की आशंका है और विवाद में राष्ट्रीय महत्व का कोई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है, या विवाद इस प्रकृति का है कि एक से अधिक राज्यों में स्थित औद्योगिक स्थापन का ऐसे विवाद में हितबद्ध होना या उससे प्रभावित होना सम्भाव्य है, और यह कि विवाद राष्ट्रीय अधिकरण द्वारा न्यायनिर्णीत होना चाहिए, वहां केन्द्रीय सरकार, चाहे वह उस विवाद के सम्बन्ध में समुचित सरकार हो या न हो, विवाद को या विवाद से संसक्त या सुसंगत प्रतीत होने वाले मामले को चाहे वह द्वितीय अनुसूची में चाहे तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी विषय के सम्बन्ध में हो, न्यायनिर्णयन के लिए, लिखित आदेश द्वारा, किसी भी समय राष्ट्रीय अधिकरण को निर्देशित कर सकेगी।

(2) जहां कि औद्योगिक विवाद के पक्षकार विवाद का निर्देश बोर्ड, न्यायालय, श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण को किए जाने के लिए विहित रीति से, चाहे संयुक्ततः चाहे पृथक्तः; आवेदन करते हैं, वहां यदि समुचित सरकार का समाधान हो जाता है कि आवेदन करने वाले व्यक्ति हर एक पक्षकार की बहुसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं तो वह तद्नुसार निर्देया करेगी।

(2क) इस धारा के अधीन श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण को किसी औद्योगिक विवाद को निर्देशित करने वाले आदेश में वह कालावधि विनिर्दिष्ट की जाएगी जिसके भीतर, ऐसा श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण उस विवाद के सम्बन्ध में अपना अधिनिर्णय समुचित सरकार को, प्रस्तुत करेगा:

परन्तु जहां ऐसा औद्योगिक विवाद किसी वयष्टिक कर्मकार से संबंधित है, वहां ऐसी कालावधि तीन मास से अधिक नहीं होगी:

परन्तु यह और कि जहां किसी औद्योगिक विवाद के पक्षकार विहित रीति से, चाहे संयुक्ततः या पृथक्तः ऐसी कालावधि के विस्तार के लिए या किसी अन्य कारण से, श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण को आवेदन करते हैं, और यदि ऐसे श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण का पीठासीन अधिकारी ऐसी कालावधि का विस्तार करना आवश्यक या समीचीन समझता है, तो वह ऐसे कारणों सहित, जो अभिलिखित किए जाएं, ऐसी कालावधि का विस्तार ऐसी अतिरिक्त कालावधि के लिए कर सकेगा, जो वह ठीक समझे:

परन्तु यह और भी कि इस उपधारा में विनिर्दिष्ट किसी कालावधि की, यदि कोई हो, संगणना करने में वह कालावधि जिसके लिए श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों को किसी सिविल न्यायालय के किसी व्यादेश या आदेश द्वारा रोक दिया गया था, अपवर्जित की जाएगी:

परन्तु यह और भी कि श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष की कार्यवाहियां केवल इस आधार पर व्यपगत नहीं हो जाएंगी कि इस उपधारा के अधीन विनिर्दिष्ट कालावधि ऐसी कार्यवाहियों के पूरा होने के पूर्व, समाप्त हो गई थी।

(3) जहां कि कोई औद्योगिक विवाद बोर्ड श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण को इस धारा के अधीन निर्देशित किया गया है वहां समुचित सरकार ऐसे विवाद के संसंग में की गई किसी ऐसी हड़ताल या तालाबन्दी को, जो निर्देश की तारीख को विद्यमान हों, चालू रखना आदेश द्वारा प्रतिषिद्ध कर सकेगी।

(4) जहां कि किसी औद्योगिक विवाद को श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण को इस धारा के अधीन निर्देशित करने वाले किसी आदेश में या किसी पश्चात्वर्ती आदेश में समुचित सरकार ने न्यायनिर्णयन के लिए विवाद के प्रश्न विनिर्दिष्ट कर दिए हैं वहां, यथास्थिति, श्रम न्यायालय या अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण अपने न्यायनिर्णय को उन प्रश्नों और उनसे आनुषंगिक विषयों तक ही सिमित रखेगा।

(5) जहां कि किसी स्थापन या किन्हीं स्थापनों से सम्पृक्त कोई विवाद श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण को इस धारा के अधीन निर्देशित किया गया है या किए जाने को है और समुचित सरकार की राय, या तो उसे इस निमित्त किए गए आवेदन पर या अन्यथा, यह हो कि विवाद इस प्रकृति का है कि उसी प्रकार के किसी अन्य स्थापन स्थापनों के समूह या वर्ग का ऐसे विवाद में हितबद्ध होना या उससे प्रभावित होना सम्भाव्य है, वहां समुचित सरकार निर्देश करते समय या उसके पश्चात् किसी भी समय, किन्तु अधिनिर्णय निवेदित किए जाने से पूर्व, उस निर्देश में ऐसे स्थापन, स्थापनों के समूह या वर्ग को सम्मिलित कर सकेगी, चाहे ऐसे सम्मिलित किए जाने के समय उस स्थापन, स्थापनों के समूह या वर्ग में कोई विवाद विद्यमान हो या न हो या उसके होने की आशंका हो या न हो।

(6) जहां कि कोई निर्देश उपधारा (1क) के अधीन राष्ट्रीय अधिकरण को किया गया है वहां, इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किसी भी श्रम न्यायालय या अधिकरण को किसी ऐसे मामले पर, जो राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष न्यायनिर्णयन के अधीन हो, न्यायनिर्णयन की अधिकारिता नहीं होगी, और तद्नुसार,-

(क) यदि राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष न्यायनिर्णयन के अधीन का कोई मामला श्रम न्यायालय या अधिकरण के समक्ष की किसी कार्यवाही में लम्बित है तो, यथास्थिति, श्रम न्यायालय या अधिकरण के समक्ष की कार्यवाही, जहां तक कि वह ऐसे मामले से संबद्ध है, राष्ट्रीय अधिकरण को

ऐसे निर्देश पर अभिखण्डित हो गई समझी जाएगी; तथा

(ख) समुचित सरकार के लिए यह विधिपूर्ण नहीं होगा कि वह राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष न्यायनिर्णयन के अधीन का कोई मामला, ऐसे मामले के सम्बन्ध में कार्यवाही के राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष लम्बित रहने के दौरान, न्यायनिर्णयन के लिए किसी श्रम न्यायालय या अधिकरण को निर्देशित करे।

स्पष्टीकरण.- इस उपधारा में, "श्रम न्यायालय" या "अधिकरण" के अन्तर्गत कोई ऐसा न्यायालय या अधिकरण या अन्य प्राधिकारी आता है जो औद्योगिक विवादों के अन्वेषण और परिनिर्धारण के सम्बन्ध में किसी भी राज्य में प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित हो।

(7) जहां कोई भी औद्योगिक विवाद, जिसके संबंध में केंद्र सरकार उपयुक्त सरकार नहीं है, राष्ट्रीय न्यायाधिकरण को भेजा जाता है, तो इस अधिनियम में किसी भी बात के बावजूद, धारा 15, धारा 17, धारा 19, धारा 33 ए में कोई संदर्भ, ऐसे विवाद के संबंध में उपयुक्त सरकार को धारा 33 बी और धारा 36 ए को केंद्र सरकार के संदर्भ के रूप में माना जाएगा, लेकिन जैसा कि पूर्वोक्त कहा गया है और जैसा कि इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है, इस अधिनियम के किसी भी अन्य प्रावधान में कोई भी संदर्भ उस विवाद के संबंध में उपयुक्त सरकार का मतलब राज्य सरकार के संदर्भ से होगा।

(8) किसी औद्योगिक विवाद के संबंध में श्रम न्यायालय, न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित कोई भी कार्यवाही केवल श्रमिक होने के कारण विवाद के किसी भी पक्ष की मृत्यु के कारण समाप्त नहीं होगी, और ऐसे श्रम न्यायालय, न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय न्यायाधिकरण ऐसी कार्यवाही पूरी करेगा और अपना पंचाट उचित सरकार को प्रस्तुत करेगा।"

10. उपरोक्त प्रावधान का अवलोकन स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि 1947 के अधिनियम के तहत श्रमिक द्वारा मांग बढ़ाने और संदर्भ मांगने के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

11. इस विषय पर सबसे पहला निर्णय **मुंबई राज्य बनाम के.पी. कृष्णन और अन्य**

एआईआर 1960 एससी 1223, मामले में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा दिया गया है, जिसमें माना गया कि अधिनियम की धारा 10 (1) सरकार को औद्योगिक विवाद को संदर्भित करने या संदर्भित करने से इनकार करने के लिए व्यापक और यहां तक कि पूर्ण विवेक प्रदान करती है। सरकार पर विवाद को संदर्भित करने का दायित्व तब तक लगाया जाता है जब तक कि वह संतुष्ट न हो कि नोटिस तुच्छ, या कष्टप्रद है या समीचीनता के विचार के लिए आवश्यक है कि संदर्भ नहीं दिया जाना चाहिए। हालाँकि, संदर्भ देने से इनकार करने का आदेश देते समय, उपयुक्त सरकार से उन कारकों पर विचार करने की अपेक्षा नहीं की जाती है जो अप्रासंगिक हैं या प्रासंगिक नहीं हैं। यहां तक कि इस प्रश्न से निपटने में कि क्या संदर्भ देना समीचीन होगा या नहीं, सरकार को दंडात्मक भावना से कार्य नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रश्न पर निष्पक्ष और उचित रूप से विचार करना चाहिए और केवल प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए। इस निर्णय का बाद में उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश सिंचाई कर्मचारी संघ बनाम **मध्य प्रदेश राज्य और दूसरा, (1985) 2 एससीसी** 102 और **वी. वीरानाजन और अन्य बनाम तमिलनाडु सरकार, (1987) 1 एससीसी** 479 मामले में पालन किया।

12. **मुंबई यूनियन ऑफ़ जर्नलिस्ट्स और अन्य बनाम द स्टेट ऑफ़ मुंबई और अन्य, एआईआर 1964 एससी** 1617, उच्चतम न्यायालय ने माना कि इस प्रश्न पर विचार करते समय कि क्या धारा 12 (5) के तहत एक संदर्भ दिया जाना चाहिए, उपयुक्त सरकार को अधिनियम की धारा 10 (1) के तहत कार्य करना होगा जो सरकार को विवाद को संदर्भित करने या इसे संदर्भित न करने का विवेक प्रदान करता है। अधिनियम की धारा 12 (5) के तहत, उपयुक्त सरकार संदर्भ न देने के कारणों को रिकॉर्ड करने के लिए बाध्य है। हालाँकि, जब मामले में कानून का प्रश्न और तथ्य का विवादित प्रश्न शामिल हो, तो उपयुक्त सरकार को उस पर अंतिम निर्णय पर पहुंचने का इरादा नहीं होना चाहिए क्योंकि यह औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा तय किया जाने वाला विषय है, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता है। उपयुक्त सरकार को विवाद की प्रथम दृष्टया योग्यता पर भी विचार करने से रोक दिया जाता है, जब वह यह निर्णय लेती है कि संदर्भ देने की उसकी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए या नहीं। आगे यह माना गया कि यदि किया गया दावा स्पष्ट रूप से तुच्छ है या स्पष्ट रूप से देर से किया गया है, तो उपयुक्त सरकार संदर्भ देने से इनकार कर सकती है।

13. **टेल्को कॉन्वॉय ड्राइवर मजदूर संघ और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य, (1989) 3 एससीसी 271 में,** उच्चतम न्यायालय ने माना कि हालांकि धारा 10 (1) के तहत एक संदर्भ बनाने के प्रश्न पर विचार करते समय, सरकार पात्र है इस बारे में राय बनाने के लिए कि क्या कोई औद्योगिक विवाद "मौजूद है या इसकी आशंका है", लेकिन यह विवाद को उसके गुणागुण के आधार पर निपटाने का पात्र नहीं है। अधिनियम की धारा 10 (1) के तहत शक्ति का प्रयोग करते समय, उपयुक्त सरकार का कार्य एक प्रशासनिक कार्य है न कि न्यायिक या अर्ध-न्यायिक कार्य। अतः यह विवाद के गुण-दोषों की गहराई में नहीं जा सकता और मामले का निर्धारण अपने ऊपर नहीं ले सकता। यह प्रश्न कि विवाद उठाने वाले व्यक्ति श्रमिक थे या नहीं, अधिनियम की धारा 10 (1) के तहत सरकार अपने प्रशासनिक कार्य का प्रयोग करते हुए इसका निर्णय नहीं कर सकती है। जाहिर है, उस मामले में विलंब का प्रश्न उच्चतम न्यायालय के सामने विचाराधीन नहीं था।

14. **रतन चंद्र सामंता और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, (1993) सप्लिमेंट (4) एससीसी 67 में,** उच्चतम न्यायालय ने माना कि नियोक्ता द्वारा छंटनी किया गया एक आकस्मिक मजदूर खुद को चूक के रूप में विलंब के कारण कानून में उपलब्ध उपचार से वंचित करता है। समय के कारण उपाय भी खो जाता है और अधिकार भी। विलंब निश्चित रूप से घातक होगा यदि इसके परिणामस्वरूप निर्णय से संबंधित भौतिक साक्ष्य खो गए और उपलब्ध नहीं हुए।

15. **वर्कमेन बनाम आई.आई.टी.आई. में साइकल्स ऑफ इंडिया लिमिटेड और अन्य, (1995) सप्लीमेंट (2) एससीसी 733,** में उच्चतम न्यायालय ने माना कि उपयुक्त सरकार के लिए प्रत्येक मामले में विवाद का संदर्भ देना अनिवार्य नहीं है जहां संदर्भ है मांग की गई है क्योंकि सरकार को पार्टियों के बीच औद्योगिक शांति और सुचारू औद्योगिक संबंधों के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए तथ्यों को देखना है और जहां संदर्भ न देने के लिए सरकार द्वारा दिए गए कारण प्रासंगिक पाए जाते हैं, न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं।

16. **मोहम्मद कवि मोहम्मद अमीन बनाम फातमाबी इब्राहिम, (1997)6 एससीसी 71 में,** उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जहां भी किसी समय सीमा निर्धारित किए बिना कोई शक्ति वैधानिक प्राधिकरण में निहित होती है, ऐसी शक्ति का प्रयोग उचित समय के भीतर किया जाना चाहिए। **एन. बालाकृष्णन बनाम एम. कृष्णमूर्ति, (1998) 7 एससीसी** 123 में,

उच्चतम न्यायालय ने माना कि किसी कानूनी उपाय को अनुचित अवधि के लिए जीवित नहीं रखा जा सकता है, भले ही क़ानून किसी सीमा का प्रावधान न करता हो।

17. **अजायब सिंह बनाम सरहिंद कोऑपरेटिव मार्केटिंग-कम-प्रोसेसिंग सर्विस सोसाइटी लिमिटेड और अन्य, (1999) 6 एससीसी 82 में,** उच्चतम न्यायालय ने माना कि लंबे समय तक विलंब के मामलों में भी, पूरी तरह या आंशिक रूप से गिरावट करके राहत दी जा सकती है। बकाया वेतन. इसने आगे कहा कि परिसीमा अधिनियम, 1963 की अनुसूची के अनुच्छेद 137 के प्रावधान अधिनियम के तहत कार्यवाही पर लागू नहीं होते हैं। ऐसे मामलों में जहां विलंब विद्यमान दिखाई देता है, औद्योगिक न्यायालय कामगार को उसकी अवैध छंटनी के संबंध में मांग उठाने की तारीख तक बकाया मजदूरी देने से इनकार करके उचित रूप से राहत दे सकता है या उचित मामलों में भुगतान के हिस्से का भुगतान करने का निर्देश दे सकता है। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने बहाली और सेवा की निरंतरता के लिए श्रम न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखा, लेकिन विवाद के संदर्भ की मांग में 7 साल की लंबी विलंब को देखते हुए, बकाया वेतन को मांग नोटिस जारी करने की तारीख से उस तारीख तक सीमित कर दिया। श्रम न्यायालय द्वारा 60% की सीमा तक पंचाट और सफल अवधि के बाद ही पूर्ण बकाया वेतन प्रदान किया गया।

18. **नेदुंगडी बैंक लिमिटेड बनाम के.पी. माधवनकुट्टी और अन्य, (2000) 2 एससीसी 455** मामले में उच्चतम न्यायालय के समक्ष चुनौती के तहत। केरल उच्च न्यायालय की खंडपीठ का निर्णय था, जिसने श्रमिकों द्वारा दायर अपील की अनुमति दी थी और विद्वान एकलपीठ के निर्णय को रद्द कर दिया था, जिसके तहत बैंक द्वारा दायर रिट याचिका को रद्द कर दिया गया था। औद्योगिक विवाद अधिनियम (संक्षेप में, "अधिनियम") की धारा 10 के तहत केंद्र सरकार द्वारा किए गए संदर्भ को रद्द करके अनुमति दी गई। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि "भले ही औद्योगिक विवाद का संदर्भ देने के लिए कोई वैधानिक सीमा अवधि नहीं है, लेकिन ऐसी शक्तियों का प्रयोग यथोचित और तर्कसंगत तरीके से किया जाना चाहिए, न कि यांत्रिक तरीके से। जब कोई विवाद समयोपरांत हो जाता है तो यह तथ्यों पर निर्भर करेगा और प्रत्येक मामले की परिस्थितियाँ। पैरा-6 में उच्चतम न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियाँ उद्धृत करने योग्य हैं:-

> "6. कानून उचित सरकार के लिए अधिनियम की धारा 10 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं

करता है। ऐसा नहीं है कि इस शक्ति का प्रयोग किसी भी समय किया जा सकता है और जो मामले सुलझ चुके हैं उन्हें पुनर्जीवित करने की शक्ति है। उचित और तर्कसंगत तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए। हमें ऐसा कोई तर्कसंगत आधार नहीं दिखता है जिसके आधार पर केंद्र सरकार ने प्रतिवादी को सेवा से बर्खास्त करने के आदेश के लगभग सात साल बीत जाने के बाद इस मामले में शक्तियों का प्रयोग किया हो। उस समय कोई संदर्भ नहीं दिया गया था औद्योगिक विवाद अस्तित्व में था या यहां तक कि कहा जा सकता था कि इसकी आशंका थी। जो विवाद समयोपरांत है वह अधिनियम की धारा 10 के तहत संदर्भ का विषय नहीं हो सकता है। किसी विवाद को कब समयोपरांत कहा जा सकता है यह तथ्यों प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा और जब मामला अंतिम हो जाता है, तो हमें यह असंगत प्रतीत होता है कि वर्तमान परिस्थितियों जैसी परिस्थितियों में अधिनियम की धारा 10 के तहत संदर्भ दिया जाए। वास्तव में यह कहा जा सकता है कि कोई मामला नहीं था विवाद उस समय लंबित था जब प्रश्न में संदर्भ दिया गया था। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तावित एकमात्र आधार यह था कि दो अन्य कर्मचारी जिन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था, उन्हें बहाल कर दिया गया था। किन परिस्थितियों में उन्हें बर्खास्त किया गया और बाद में बहाल किया गया, इसका कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। औद्योगिक विवाद उठाने के लिए प्रतिवादी द्वारा उठाई गई मांग प्रथम दृष्टया खराब और अक्षम थी।"

19. **सपन कुमार पंडित बनाम यू.पी. राज्य विद्युत बोर्ड और अन्य, (2001) एससीसी 222**, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय को उच्चतम न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई, जिसने 15 वर्ष के विलंब के आधार पर उपयुक्त सरकार द्वारा पारित संदर्भ आदेश को रद्द कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने माना कि औद्योगिक विवाद का संदर्भ देने की सीमा अवधि विवाद के अस्तित्व के साथ व्यापक है। विवाद के अस्तित्व के बारे में राय अकेले सरकार को बनानी है, किसी और को नहीं। उ.प्र. औद्योगिक विवाद अधिनियम, जो अधिनियम की धारा 10 की धारा 4-क के उल्लेख के समान है, उच्चतम न्यायालय ने निर्णय के पैरा 8 और 9 में निम्नानुसार कहा:-

"8. उपरोक्त धारा लगभग औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 के अनुरूप है, और इन दोनों प्रावधानों के बीच का अंतर इस मामले में मुद्दे से संबंधित नहीं है।

हालाँकि, किसी विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए संदर्भित करने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है, क्या कोई राज्य सरकार किसी ऐसे विवाद को पुनर्जीवित कर सकती है जो लंबे समय के अंतराल के बाद स्तब्ध हो गया था और उसे न्यायनिर्णयन के लिए संदर्भित करके फिर से जागृत किया जा सकता है? भाग में किसी भी समय उपयोग किए गए शब्द प्रथम दृष्टया बिना किसी सीमा के अवधि के संकेतक हैं। लेकिन शक्ति को अनंत बनाने वाली ऐसी व्याख्या पांडित्यपूर्ण होगी। इस उपधारा में ही यह संकेत देने के लिए अंतर्निहित साक्ष्य हैं कि समय की कुछ सीमाएँ हैं। जिन शब्दों पर सरकार की राय है कि कोई औद्योगिक विवाद मौजूद है या आशंका है, उन्हें किसी भी समय शब्दों के साथ जोड़कर पढ़ा जाना चाहिए। वे एक तरह से एक-दूसरे के पूरक हैं।

किसी औद्योगिक विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए संदर्भित करने की सरकार की शक्ति में समय की एक सीमा है और वह यह है कि यह तभी तक किया जा सकता है जब तक विवाद मौजूद है। दूसरे शब्दों में, किसी भी समय स्थायी अभिव्यक्ति द्वारा परिकल्पित अवधि औद्योगिक विवाद के ग्रहण के साथ समाप्त हो जाती है। अतः, इसका मतलब यह है कि यदि विवाद उस दिन मौजूद था जब सरकार द्वारा संदर्भ दिया गया था, तो यह निर्धारित करने के लिए विवाद शुरू होने के बाद से बीते वर्षों की संख्या का पता लगाना बेकार है कि क्या विलंब से सरकार की शक्ति समाप्त हो गई होगी।

9. अतः असली परीक्षा यह है कि क्या निर्णय के लिए संदर्भ की तारीख पर औद्योगिक विवाद अस्तित्व में था? यदि उत्तर नकारात्मक है तो संदर्भ देने की सरकार की शक्ति समाप्त हो जाएगी। दूसरी ओर, यदि उत्तर सकारात्मक है तो सरकार अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकती थी, चाहे विवाद शुरू होने के बाद से कितनी भी अवधि बीत चुकी हो। इसके

अलावा, इस संबंध में सरकार के निर्णय को इस संभावना पर सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता है कि कोई अन्य पक्ष क्या सोचेगा चाहे कोई विवाद मौजूद हो या नहीं। यह धारा इंगित करती है कि यदि सरकार की राय में विवाद मौजूद है तो सरकार संदर्भ दे सकती है। एकमात्र प्राधिकारी जो ऐसी राय बना सकती है वह सरकार है। यदि सरकार संदर्भ देने का निर्णय लेती है तो यह अनुमान लगाया जाएगा कि सरकार की राय में ऐसा कोई विवाद था।

20. **एस.एम. में निलजकर और अन्य बनाम टेलीकॉम डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, कर्नाटक, (2003) 4 एससीसी** 27 में उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थीगण का तर्क यह था कि अपीलकर्ता श्रमिकों द्वारा विवाद उठाने में केवल विलंब के कारण, उच्च न्यायालय द्वारा राहत देने से इनकार करना उचित नहीं था। हालाँकि, उच्चतम न्यायालय ने मामले के तथ्यों में उस तर्क को बरकरार रखा, फिर भी **शालीमार वर्क्स लिमिटेड बनाम वर्कमेन, एआईआर 1959 एससी** 1217 में अपने पहले के निर्णय पर भरोसा करते हुए, उच्चतम न्यायालय ने माना कि केवल इसलिए कि औद्योगिक विवाद अधिनियम विवाद उठाने की सीमा प्रदान नहीं करता है, इसका मतलब यह नहीं है कि विवाद किसी भी समय और विलंब और कारणों की परवाह किए बिना उठाया जा सकता है। औद्योगिक न्यायाधिकरण को विवादों के संदर्भ के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं है; फिर भी यह उचित है कि विवादों के उत्पन्न होने के बाद और सुलह की कार्यवाही विफल होने के बाद उन्हें यथाशीघ्र संदर्भित किया जाना चाहिए, खासकर तब जब विवाद श्रमिकों के निर्वहन से संबंधित हों।

21. **हरियाणा राज्य सहकारी समिति में भूमि विकास बैंक बनाम नीलम, (2005) 5 एससीसी** 91 में उच्चतम न्यायालय ने माना कि यद्यपि न्यायालय उस समय सीमा की अवधि का संज्ञान नहीं ले सकता जब विधान इसे निर्धारित नहीं करता है, जैसा कि अजायब सिंह (सुप्रा.) में देखा गया था, लेकिन इसका मतलब यह है कि प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के बावजूद, संदर्भ बनाते समय उपयुक्त सरकार द्वारा पुराने दावे पर विचार किया जाना चाहिए या ऐसे मामले में जहां ऐसा संदर्भ दिया जाता है, श्रमिक श्रम न्यायालय के हाथों राहत का पात्र होगा।

22. **यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम बनाम बाबू राम, (2006) 5 एससीसी** 433, में उच्चतम न्यायालय ने माना कि जहां तक संदर्भ मांगने में विलंब का प्रश्न है, उक्त प्रश्न के

निर्धारण के लिए सार्वभौमिक अनुप्रयोग का कोई फार्मूला निर्धारित नहीं किया जा सकता है, यह प्रत्येक के तथ्यों पर निर्भर करेगा। व्यक्तिगत **इंजीनियर, सीएडी, कोटा बनाम धन कुँवर, (2006) 5 एससीसी** 481 में उच्चतम न्यायालय ने यह भी माना कि यह ध्यान दिया जा सकता है कि जहां तक संदर्भ मांगने में विलंब का प्रश्न है, सार्वभौमिक अनुप्रयोग का कोई सूत्र निर्धारित नहीं किया जा सकता है। यह प्रत्येक व्यक्तिगत मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा।

23. **राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और अन्य बनाम जनरल एम्प्लॉइज एसोसिएशन और अन्य, (2007) 5 एससीसी** 273 में उच्चतम न्यायालय ने माना कि उच्च न्यायालय सीधे संबंधित सरकार को विवाद को संदर्भित करने का निर्देश नहीं दे सकता है। यह उपयुक्त सरकार पर निर्भर करता है कि वह विवाद को संदर्भित करने का निर्णय लेने से पहले प्रासंगिक कारकों पर अपना दिमाग लगाए और विवाद के अस्तित्व के बारे में खुद को संतुष्ट करे।

24. **कृषि उत्पादन मंडी समिति, मंगलोर बनाम पहल सिंह, (2007) 12 एससीसी** 193 में उच्चतम न्यायालय एक ऐसे मामले से निपट रहा था जहां छंटनी की तारीख के 18 साल बाद औद्योगिक विवाद उठाया गया था। श्रम न्यायालय ने प्रबंधन द्वारा सेवा समाप्ति को अवैध घोषित कर दिया और कामगार को सेवा की निरंतरता और बकाया वेतन के साथ बहाल करने का निर्देश दिया। उच्चतम न्यायालय ने माना कि श्रम न्यायालय इस बात पर विचार करने के लिए बाध्य है कि क्या इस तथ्य के मद्देनजर श्रमिक के पक्ष में कोई राहत दी जा सकती है कि औद्योगिक विवाद 18 साल बाद उठाया गया था। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह कानून का सुस्थापित सिद्धांत है कि "विलंब समता को पराजित करता है"। आगे यह माना गया कि श्रम न्यायालय औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 11-क के तहत अपने व्यापक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है, लेकिन ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। सभी पिछले वेतन के साथ बहाली की राहत प्रासंगिक कारकों पर विचार किए बिना नहीं दी जानी चाहिए, केवल इसलिए कि ऐसा करना वैध होगा। उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के निर्णय को रद्द कर दिया और अपील की अनुमति दे दी।

25. **कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम रवि कुमार, (2009) 13 एससीसी** 746 में, उच्चतम न्यायालय ने माना कि संदर्भ मांगने और सेवा समाप्ति के आदेश को चुनौती देने

में 14 साल की विलंब घातक था क्योंकि पर्यवेक्षण करने वाले व्यक्ति से बाद में साबित करने की उम्मीद की जा सकती थी। 14 वर्ष जब प्रतिवादी ने काम नहीं किया या उसने एक वर्ष में 240 दिन काम नहीं किया या कि उसने स्वेच्छा से काम छोड़ दिया। चूंकि संदर्भ समयोपरांत था, अतः इसे केवल इसी आधार पर खारिज कर दिया जाना चाहिए था। इस प्रकार मानते हुए, उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के निर्णय को रद्द कर दिया और श्रम न्यायालय के निर्णय को बहाल कर दिया जिसने संदर्भ को खारिज कर दिया था।

26. **रहमान इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, (2016) 12 एससीसी 420 में,** उच्चतम न्यायालय के समक्ष उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें उचित सरकार को उठाए गए विवाद को संदर्भित करने के लिए अनिवार्य निर्देश दिया गया था। न्यायनिर्णयन के लिए यह तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय के आदेश ने वस्तुतः सरकार से इस मुद्दे पर गौर करने का विवेक छीन लिया है कि क्या कोई संदर्भित विवाद है। इस तर्क को बरकरार रखते हुए, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ऐसा नहीं है कि सरकार को उनके द्वारा प्राप्त प्रत्येक याचिका का संदर्भ देकर डाकघर के रूप में कार्य करना है। सरकार यह देखने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में है कि क्या निर्णय के लिए संदर्भित करने लायक कोई विवाद मौजूद है। पैरा-3 में उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार कहा:-

> "3. हमें विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुति में बल मिलता है। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की योजना में, ऐसा नहीं है कि सरकार को डाकघर के रूप में कार्य करना है उनके द्वारा प्राप्त प्रत्येक याचिका को संदर्भित करके सरकार यह देखने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में है कि क्या न्यायनिर्णयन के लिए संदर्भित करने लायक कोई विवाद मौजूद है। इसमें कोई संदेह नहीं है, सरकार मामले की योग्यता के आधार पर निष्कर्ष निकालने और संदर्भ को अस्वीकार करने की पात्र नहीं है। सरकार को संबंधित कारकों पर अपना दिमाग लगाने के बाद खुद को संतुष्ट करना होगा और निर्णय के लिए इसे संदर्भित करने का निर्णय लेने से पहले विवाद के अस्तित्व के बारे में खुद को संतुष्ट करना होगा। केवल मामले में, न्यायिक जांच पर, न्यायालय को पता चलता है कि इनकार करने से इनकार कर दिया गया

है। सरकार द्वारा विवाद का संदर्भ बनाना अप्रासंगिक कारकों पर अनुचित है, न्यायालय सरकार को संदर्भ बनाने का निर्देश जारी कर सकती है।"

27. इस याचिका से जुड़े मुद्दे और विवाद का निर्णय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की बड़ी पीठ द्वारा **श्री जय सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य CWP No** 2190/2020 के मामले में पहले ही किया जा चुका है। इस मुद्दे का उत्तर पैरा 28 में इस प्रकार है:

> "28. अतः, ऊपर चर्चा की गई मिसालों की श्रृंखला से कानून के निम्नलिखित सिद्धांतों को हटाया जा सकता है, जो अधिनियम की धारा 10(1) के तहत औद्योगिक विवाद को श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरण को संदर्भित करने की मांग/करने में विलंब के प्रभाव को दर्शाता है:-
>
> i) अधिनियम की धारा 10(1) के तहत औद्योगिक विवाद का संदर्भ देने के प्रश्न से निपटने के दौरान उपयुक्त सरकार का कार्य एक प्रशासनिक कार्य है, न कि न्यायिक या अर्ध-न्यायिक कार्य।
>
> ii) सरकार को औद्योगिक विवाद का संदर्भ देने के प्रश्न पर निर्णय लेने से पहले एक निश्चित राय बनानी होगी कि ऐसा विवाद है या नहीं।
>
> iii) अधिनियम की धारा 10(1) के अर्थ में औद्योगिक विवाद मौजूद है या नहीं, इसका निर्णय अकेले उपयुक्त सरकार द्वारा किया जा सकता है, न कि इस न्यायालय सहित किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा।
>
> iv) अधिनियम की धारा 10(1) के तहत औद्योगिक विवाद के संदर्भ में निर्णय लेने या न करने का निर्णय लेने के प्रशासनिक कार्य का निर्वहन करने में उपयुक्त सरकार को प्रासंगिक विचारों पर अपना दिमाग लगाना होगा और कार्रवाई नहीं करनी होगी।
>
> v) यह राय बनाते समय कि क्या औद्योगिक विवाद मौजूद है या इसकी आशंका है, उपयुक्त सरकार विवाद को गुणागुण के आधार पर निपटाने की पात्र नहीं है।
>
> vi) यह विलंब अपने आप में उचित सरकार को औद्योगिक विवाद का संदर्भ देने की उपयुक्तता की जांच करने की शक्ति से वंचित नहीं करती है,

लेकिन विलंब निश्चित रूप से मूल प्रश्न का निर्णय करने के लिए प्रासंगिक होगी कि क्या औद्योगिक विवाद "अस्तित्व में है" जिसमें यह भी शामिल है यह पता लगाने का निर्णय कि क्या विलंब के कारण विवाद का अस्तित्व समाप्त हो गया है या अस्तित्व समाप्त हो गया है या समयोपरांत हो गया है।

vii) कि कोई विवाद जीवित है या नहीं, समयोपरांत हो गया है या अस्तित्वहीन हो गया है, यह हमेशा प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा और इसके लिए सार्वभौमिक अनुप्रयोग का कोई नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

viii) भले ही अधिनियम की धारा 10(1) उपयुक्त सरकार को इस प्रश्न पर "किसी भी समय" राय बनाने का अधिकार देती है कि क्या कोई "औद्योगिक विवाद" "मौजूद है या आशंका है", और इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है ऐसा निर्णय लेना, फिर भी ऐसी शक्ति का प्रयोग उचित सरकार द्वारा उचित समय के भीतर किया जाना चाहिए।

ix) कि औद्योगिक विवाद का संदर्भ देने की अवधि विवाद के अस्तित्व के साथ सह-विस्तारित है क्योंकि "अस्तित्व" या "विवाद की आशंका" का तथ्य विवाद की जीवंतता पर विलंब के प्रभाव से निर्धारित होता है।

x) उचित सरकार, औद्योगिक विवाद का संदर्भ देने के निर्णय पर पहुंचने में या अन्यथा, विलंब के संदर्भ में, यह जांच कर सकती है कि क्या कामगार या संघ उचित मंच के समक्ष मामले को लेकर आंदोलन कर रहे हैं ताकि विवाद को बरकरार रखा जा सके। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसे मामले में जहां ऐसी कार्रवाई शुरू नहीं की गई है, विवाद का अस्तित्व समाप्त हो गया है।

xi) उचित सरकार, अधिनियम की धारा 10(1) के अनुसार, संदर्भ बनाने के प्रश्न पर "किसी भी समय" निर्णय ले सकती है, इस प्रकार इसका अर्थ यह है कि ऐसा निर्णय लेने में कोई सीमा नहीं है और अनुच्छेद के प्रावधान परिसीमा अधिनियम, 1963 की अनुसूची के 137 ऐसी

कार्यवाहियों पर लागू नहीं होते हैं।

xii) संदर्भ देने के प्रश्न पर निर्णय लेते समय उपयुक्त सरकार को कर्मचारी को सुनवाई का विस्तृत अवसर प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मांग करने में विलंब के लिए उसके स्पष्टीकरण पर विचार करना उसका दायित्व है।

xiii)ऐसे मामलों में जहां उपयुक्त सरकार औद्योगिक विवाद का संदर्भ देने के प्रश्न की जांच करते समय इस निर्णय पर पहुंचती है कि विलंब के कारण विवाद समाप्त हो गया है या अस्तित्व में है, इसके लिए साक्ष्य की विस्तृत जांच की आवश्यकता होगी, यह औद्योगिक विवाद का संदर्भ देते समय, प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय किए जाने वाले इस पहलू पर अतिरिक्त प्रश्न तैयार कर सकते हैं, साथ ही द्वितीयक मुद्दे के रूप में तय किए जाने वाले औद्योगिक विवाद का भी संदर्भ दे सकते हैं।

xiv) ऐसे मामले में भी जहां लंबे विलंब के बाद औद्योगिक न्यायालय को संदर्भ दिया गया है, ऐसा न्यायालय पिछले वेतन के पूरे या आंशिक हिस्से को कम करके राहत देने का पात्र होगा।

xv) यहां तक कि जब किसी मामले में उचित सरकार द्वारा अत्यधिक और अस्पष्टीकृत विलंब के बाद भी कोई संदर्भ दिया जाता है, तो औद्योगिक न्यायालय संदर्भ वापस करने का पात्र होगा क्योंकि ऐसा न्यायालय औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 11-क के तहत अपने व्यापक क्षेत्राधिकार का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करता है और यह विचार करना दायित्व है कि क्या ऐसी स्थिति में कामगार को कोई राहत दी जा सकती है।

28. विधायिका की मंशा को 1947 के अधिनियम की धारा 10 (1) के तहत प्रयुक्त शब्दों से जाना जाता है, अतः, उपयुक्त सरकार के लिए विधायिका की मंशा से परे जाना अनुमत खुला नहीं है और ऐसा नहीं किया जा सकता है यह माना गया कि विधायिका ने वैधानिक प्रावधान की व्याख्या करते समय सीमा अवधि प्रदान न करके गलती की है। इस प्रकार, यह सुरक्षित रूप से माना जा सकता है कि यह उचित सरकार के लिए खुला नहीं होगा,

जबकि अधिनियम की धारा 10 (1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह तय करना होगा कि श्रमिक का दावा समयोपरांत है या नहीं।

29. अतः, यह स्पष्ट है कि विलंब स्वयं संदर्भ देने से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति विलंब का दोषी है, तो यह श्रम न्यायालय के लिए आधार हो सकता है कि वह या तो कोई राहत देने से इनकार कर दे या पिछली मजदूरी की राहत देने से इनकार कर दे। संदर्भ दिया जाना चाहिए या नहीं, इस प्रश्न का निर्णय करते समय सरकार निर्णायक प्राधिकारी की भूमिका नहीं निभा सकती है।

30. विवाद का संदर्भ देते समय, उपयुक्त सरकार प्रारंभिक मुद्दे के रूप में श्रम न्यायालय द्वारा तय किए जाने वाले 'विलंब' के प्रश्न को तैयार कर सकती है, साथ ही साथ द्वितीयक मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए औद्योगिक विवाद का संदर्भ भी दे सकती है।

31. परिणामस्वरूप, आक्षेपित आदेश को रद्द और खारिज किया जाता है और सरकार को विवाद का संदर्भ बनाने का निर्देश दिया जाता है।

32. उपरोक्त निर्देशों के साथ याचिका का निपटारा किया जाता है।

(अनूप कुमार ढंड), न्यायमूर्ति

Pcg/101

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल, द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।